

रेल, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग से उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) कुछ ऐसी प्रेस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं जिनमें बिहार के विश्वविद्यालयों में परिणामों वितीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं, आदि में धोखाधड़ी का उल्लेख किया गया है। क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालय राज्य विधान के अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे हैं अतः इन आरोपों की जांच करना विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा बिहार सरकार का काम है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अप्रशिक्षित रसोई-प्रबन्धक

2453. श्री कलराज मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रसोई घर में कार्यरत रसोई-प्रबन्धक अप्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी रसोई प्रबन्धकों को अन्य स्थानों पर लगाया जाता है जिसके कारण भोजन और नाश्ता बहुत देर से दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आहार विशेषज्ञ (डायटिशियन) भी खाद्य वस्तुओं पर उचित ध्यान नहीं देते जिसके कारण मरीजों को तकलीफ उठानी पड़ती है ; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री नोहार रंजन लस्कर) : (क) रसोई प्रबन्धक के भर्ती नियमों के अनुसार यह पद उस अवसर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिन्होंने इस ग्रेड

में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और रसोई प्रबन्ध में अनुभव रखते हों। किसी डिप्लोमा की कोई अपेक्षा निर्धारित नहीं की गई है।

इस अस्पताल में काम कर रहे दो रसोई प्रबन्धकों में से एक के पास खान पान का डिप्लोमा है लेकिन उसे डाक्टरों सलाह पर रसोईघर से अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। तथापि नाश्ता और भोजन बिल्कुल समय पर दिये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सड़े-गले फलों की सप्लाई

2454. श्री कलराज मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस निरीक्षण अधिकारी ने डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फलों की सप्लाई करने वाले ठेकेदार के पास सड़े-गले फल पाये थे और सख्ती की थी, उसे जापन दिया गया था, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) दोषी ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नोहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Development of Kakinada Port into a Major Port

2455. SHRI B. KRISHNA MOHAN BHAMIDIPATI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have under its consideration any proposal for the development of Kakinada Port into a Major Port; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) No.

(b) Does not arise.

Regional Office of University Grants Commission in South

2456. **SHRI B. KRISHNA MOHAN BHAMIDIPATI:** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state whether Government have under its consideration any proposal for opening a regional office of University Grants Commission in the South?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): There is at present no such proposal under consideration of the Government.

Survey into the problems of disabled persons

2457. **SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government have conducted a survey to find out the basic problems of disabled persons in the country; and

(b) if so, what are the details thereof and the progress made so far in the matter to solve the problems of disabled persons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) During the 1981 Census the incidence of total disability in the area of the

blind, the deaf and crippled has been assessed. National Sample Survey Organisation is conducting a comprehensive sample survey on disabled persons. Though no formal study of the basic problems of the disabled has been done at national level, their problems mainly relate to prevention, early detection, treatment, education, training, rehabilitation, placement and integration in society.

The Government of India have taken up several schemes to tackle these problems, for instance, national programme of prevention and control of blindness, expanded immunization programme, treatment facilities in various medical institutions, assistance to voluntary organisations to promote education, training and rehabilitation services for disabled, differential rate of interest on loans, petrol subsidy, reservation in Group 'C' and Group 'D' posts/services in central services and also in public sector undertakings, special employment exchanges, vocational rehabilitation centres for the disabled, scheme of integrated education for disabled, national awards to best handicapped workers/employers and also to placement officers, National awards to individual(s) and institution(s) for work done for the cause of the handicapped, aids and appliances to disabled etc.

Eradication of Leprosy

2458. **SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any programme to eradicate leprosy in the next 20 years; and

(b) if so, what are the details in this regard and the progress made so far in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b) National Leprosy Control Programme